



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430]
No. 430]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 1997/श्रावण 10, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 1997/SRAVANA 10, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अगस्त, 1997

का. आ. 540(अ).—यतः;

- 1) 9 अगस्त, 1996 को आयोजित अंतर-एक्सचेंज समन्वय समूह (इसमें इसके पश्चात् "अ.ए.स.स." के रूप में निर्दिष्ट) की कार्यकारिणी समिति की बैठक में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट) ने भाग लेने वाले स्टॉक एक्सचेंजों, जिनके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज (इसमें इसके पश्चात् "उ.प्र.स्टा.ए." के रूप में निर्दिष्ट) है, के प्रतिनिधियों से स्टॉक एक्सचेंजों के शासी मंडलों के लोक प्रतिनिधि निदेशकों और एक्सचेंज के अनुच्छेद में यथा अंतर्विष्ट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त कानूनी समितियों के लोक प्रतिनिधियों की अवधि और निरन्तरता से संबंधित मामले पर परामर्श किया; और
- 2) 9 अगस्त, 1996 को अ.ए.स.स. की बैठक में सहभागियों के इस सर्वसम्मत विचार को ध्यान में रखने के पश्चात्, कि स्टॉक एक्सचेंजों की कानूनी समितियों के लोक प्रतिनिधि निदेशकों और लोक प्रतिनिधियों को उस समय तक बने रहना चाहिए जब तक नए लोक प्रतिनिधि उनके स्थान पर नियुक्त नहीं कर लिए जाते हैं, बोर्ड ने, इसके परिपत्र सन्दर्भ सं. एस एम डी/आर सी जी/3737/96 दिनांक 13 अगस्त, 1996 के अनुसार, सभी स्टॉक एक्सचेंजों, जिनके अन्तर्गत उ.प्र.स्टा.ए. है, को कथित अ.ए.स.स. की बैठक के विनिश्चयों

के निबंधनों के अनुसार लोक प्रतिनिधियों की अवधि से संबंधित उनके नियमों / संगम-अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी थी ; और

- 3) दिनांक 13 अगस्त, 1996 के कथित परिपत्र के जवाब में, देश के सभी स्टॉक एक्सचेंजों, जिनके अन्तर्गत उ.प्र.स्टा.ए. है, ने उनके अपने-अपने नियमों और संगम-अनुच्छेद में संशोधन करने की रजामंदी अभिव्यक्त की थी और उ.प्र.स्टा.ए. ने, इसके पत्र सन्दर्भ सं. यू पी एस ई/96-97/7360 दिनांक 07 अक्तूबर, 1996 के अनुसार, बोर्ड को उनके संगम-अनुच्छेद में प्रस्तावित संशोधन भेज दिए थे ; और
- 4) बोर्ड ने, उ.प्र.स्टा.ए. को फैक्स द्वारा भेजे गए इसके पत्र सन्दर्भ सं. एस एम डी/आर सी जी/ए एस डी/5306/96 दिनांक 14 नवम्बर, 1996 के अनुसार, लोक प्रतिनिधियों की अवधि से संबंधित उ.प्र.स्टा.ए. के संगम-अनुच्छेद के अनुच्छेद 98(i) में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित कर दिया था और उ.प्र.स्टा.ए. द्वारा अनुच्छेदों के संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह उ.प्र.स्टा.ए. को दी थी, जैसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ; और
- 5) लोक प्रतिनिधियों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 98(i) में प्रस्तावित संशोधन के लिए बोर्ड का अनुमोदन 21 दिसम्बर, 1996 को आयोजित उ.प्र.स्टा.ए. के वार्षिक साधारण अधिवेशन में लिया था, जहाँ पर, कथित संशोधन सदस्यों द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ था और इसलिये इसे, तद्द्वारा ऐसा संशोधन करने के एक्सचेंज के इन्कार को उपदर्शित करते हुए छोड़ दिया गया था; और
- 6) बोर्ड ने, इसके पत्र सन्दर्भ सं. एस एम डी/ओ पी जी/आर सी जी/1428/97 दिनांक 04 अप्रैल, 1997 के अनुसार, उ.प्र.स्टा.ए. को लोक प्रतिनिधियों की अवधि से संबंधित इसके संगम-अनुच्छेद के अनुच्छेद 98(i) को संशोधित करने का निदेश देते हुए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन एक आदेश पारित किया था। इसके अतिरिक्त, उ.प्र.स्टा.ए. को सूचित किया गया था कि आदेश के जारी करने की तारीख के दो मास के भीतर एक्सचेंज द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल होने पर, भाप्रविबो, उ.प्र.स्टा.ए. के संगम-अनुच्छेद के अनुच्छेद 98(i) को अपनी ओर से, आदेश में प्रस्तावित प्ररूप में संशोधित करेगा ; और
- 7) उ.प्र.स्टा.ए. ने, इसके पत्र सन्दर्भ सं. यू पी एस ई/97-98/2224 दिनांक 05 मई, 1997 के अनुसार, बोर्ड को सूचित किया था कि एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के दिनांक 04 अप्रैल, 1997 के ऊपर उल्लिखित आदेश में यथा अंतर्विष्ट एक्सचेंज के संगम-अनुच्छेद में संशोधन के लिए एक विशेष संकल्प को पारित करने और समर्थ बनाने के लिए 24 मई, 1997 को असामान्य साधारण अधिवेशन (अ.सा.अ.) बुलाया था । तथापि, फैक्स द्वारा भेजे गए उनके पत्र दिनांक 24 मई, 1997 के अनुसार, उ.प्र.स्टा.ए. ने बोर्ड को सूचित किया

था कि उक्त अ.सा.अ. में कथित संकल्प पर गुप्त मतदान द्वारा मत प्राप्त किया गया था और जो विफल रहा ; और

8) उ.प्र.स्टा.ए. बोर्ड के आदेश दिनांक 04 अप्रैल, 1997 की, कथित आदेश में निर्निर्दिष्ट सम्भावना के भीतर अनुपालना करने में असफल रहा है ।

9) बोर्ड की यह राय है कि विनिधानकर्ताओं और पूँजी बाज़ार के हितों में, और साथ ही लोक हित में, इस आदेश में उपदर्शित रीति में उ.प्र.स्टा.ए. के संगम-अनुच्छेद के अनुच्छेद 98(i) को, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कारणों के लिए, संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है, अर्थात् :-

- i. उ.प्र.स्टा.ए. के संगम-अनुच्छेद का विद्यमान अनुच्छेद 98(i) यह उपबंध करता है कि नामांकन के पश्चात् एक वर्ष की समाप्ति पर या अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन के दिन, जो भी पूर्वतम है, लोक प्रतिनिधियों की अवधि समाप्त होती है। इस पद्धति से यह समस्या आती है कि यदि एक्सचेंज, सही समय पर नए लोक प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकेगी जहाँ वर्तमान लोक प्रतिनिधियों की अवधि के अवसान और एक्सचेंज के लिए नए लोक प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बीच एक अंतर ल आ जायेगा । अतएव, एक्सचेंज के पास शासी मंडल के लोक प्रतिनिधि नहीं होंगे और एक्सचेंज का प्रशासन केवल दलालों की समानावृत्ति करते हुए एक शासी मंडल द्वारा किया जायेगा । ऐसी स्थिति का परिणाम इस विनिश्चय हो सकेगा कि विनिधानकर्ताओं और अन्य दलाल-सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का । इस मुख्य कारण से, बोर्ड ने विगत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि शासी मंडल का गठन ऐसा है कि उसमें पर्याप्त लोक प्रतिनिधि समाविष्ट हैं एक निर्देश जारी किया था ।
- ii. एक्सचेंजों के शासी मंडलों तथा एक्सचेंजों द्वारा नियुक्त कार्परेट समितियों में लोक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति, विनिधान करने वाली साधारण जनता के हितों और एक्सचेंज के निर्विघ्न दैनिक कार्यों के लिए हानिकारक है ।
- iii. इसके सिवाय, बोर्ड देश में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के शासी मंडल के गठन संबंधी नियमों, विनियमों और उप-विधियों में एकसूत्रता बनाए रखना वांछनीय समझता है ।

इसलिये अब, बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति अधिनियम (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 29क के अधीन जारी इसकी अधिसूचना सं. एस नो/372/3 दिनांक 03 जुलाई, 1997 के अधीन बोर्ड को प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ एडिटेड कथित अधिनियम की धारा 8 की

उप-धारा (2) द्वारा इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उ.प्र.स्टा.ए. के संगम-अनुच्छेद के विद्यमान अनुच्छेद 98(1) को निम्नलिखित नए अनुच्छेद 98(1) द्वारा प्रतिस्थापित करता है :-

“98(1) निदेशक बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन, लोक प्रतिनिधियों के रूप में निर्दिष्ट ऐसे 3 (तीन) व्यक्तियों से अधिक को नामनिर्देशित नहीं करेगा जो प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक वृत्तिक सक्षमता और अनुभव रखने वाले सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और जो परिक्षेत्र में लोक ख्यातिप्राप्त है। इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस समय तक निरंतर पद धारण करेंगे जब तक उनके स्थान पर नए लोक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर लिए जाते हैं।”

यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 98(i) में विद्यमान दो परंतुक वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं और नए रूप में परिवर्धित अनुच्छेद 98(i) के पश्चात् जोड़े जाएँगे।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/स्टा.ए./977/97]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st August, 1997

S.O. 540(E).—Whereas;

- 1) In the meeting of the Executive Committee of Inter-Exchange Co-ordination Group (**hereinafter referred to as “IECG”**) held on August 09, 1996, Securities and Exchange Board of India (**hereinafter referred to as “the Board”**) consulted the representatives of the participating stock exchanges, including Uttar Pradesh Stock Exchange (**hereinafter referred to as “UPSE”**) on the issue pertaining to the term and continuity of Public Representative Directors on the Governing Board of Stock Exchanges and Public Representatives on the Statutory Committees appointed by the exchange as contained in the Articles of the exchange; AND
- 2) After taking into account, the unanimous view of the participants in the IECG meeting on August 09, 1996, that the Public Representative Directors and Public Representatives on the Statutory Committees of the stock exchanges should continue till the time new Public Representatives are appointed in their place, the Board, vide its circular Ref. No. SMD/RCG/3737/96 dated August 13, 1996, had advised all the stock exchanges, including UPSE, to take steps to amend their Rules/Articles of Association relating to the term of Public Representatives in terms of the decisions of the said IECG meeting; AND

- 3). In response to the said circular dated August 13, 1996, all stock exchanges in the country, including UPSE, had expressed their willingness to carry out the amendments to their respective Rules and Articles of Association and UPSE had, vide its letter Ref. No. UPSE/96-97/7360 dated October 07, 1996, forwarded to the Board proposed amendments to their Articles of Association; AND
- 4). The Board had, vide its letter by fax Ref. No. SMD/RCG/ASD/5306/96 dated November 14, 1996 to UPSE, approved the proposed amendment to Article 98(i) of the Articles of Association of UPSE relating to the term of Public Representatives and advised UPSE to take necessary steps for amendment of the Articles by UPSE, as approved by SEBI; AND
- 5). The Board's approval to the proposed amendment to Article 98(i) relating to the term of Public Representatives was taken up at the Annual General Meeting of UPSE held on December 21, 1996, wherein, the said amendment was not approved by the members and hence dropped, thereby indicating the exchange's refusal to carry out such an amendment; AND
- 6). The Board had, vide its letter Ref. No. SMD/OPG/RCG/1428/97 dated April 04, 1997, issued an Order under Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 directing UPSE to amend Article 98(i) of its Articles of Association relating to the term of Public Representatives. Further, UPSE was informed that on failure by the exchange to comply with the above Order within two months of the date of issue of the Order, SEBI shall, on its own, amend Article 98(i) of the Articles of Association of UPSE, in the form proposed in the Order; AND
- 7). UPSE had, vide its letter Ref. No. UPSE/97-98/2224 dated May 05, 1997, informed the Board that Board of Directors of the exchange had convened an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) on May 24, 1997, for passing and enabling a special resolution for amendment in the Articles of Association of the exchange as contained in the Board's above mentioned Order dated April 04, 1997. However, vide their letter by fax dated May 24, 1997, UPSE informed the Board that the said resolution was put to vote in the above EGM and defeated by secret voting; AND

8). UPSE has failed to comply with the Board's Order dated April 04, 1997, within the time period specified in the said Order.

9). The Board is of the opinion that in the interests of the investors and the capital markets, as also in public interest, it is necessary and expedient to amend the Article 98(i) of the Articles of Association of UPSE in the manner indicated in this Order, inter alia, for the following reasons, namely :-

- i. the existing Article 98(i) of the Articles of Association of UPSE provides that the term of Public Representatives expires at the end of one year after nomination or on the day of the next Annual General Meeting, whichever is earlier. The problem faced with this practice is that if the exchange does not submit proposals for the appointment of new Public Representatives, well in time, a situation may arise wherein there may be a gap between the expiry of the term of present Public Representatives and appointment of new Public Representatives for the exchange. Hence, the exchange may not have Public Representatives on the Governing Board and the exchange may be administered by a Governing Board comprising of brokers only. Such a situation might result in decisions which adversely affect the investors and other broker-members. For this very reason, the Board had issued a directive in the past to ensure that the constitution of the Governing Board is such that it comprises of adequate public representatives.
- ii. the absence of Public Representatives on the Governing Boards of exchanges, as well as on the Statutory Committees appointed by the exchanges, is detrimental to the interests of the general investing public, and smooth day to day functioning of the exchange.
- iii. moreover, the Board finds it desirable to maintain uniformity in the Rules, Regulations and Bye-laws regarding composition of the Governing Board of various stock exchanges in the country.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred to it by sub-section (2) of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with the powers delegated to the Board by the Central Government under its notification no. SO/573(E) dated July 03, 1992, issued under Section 29A of the said Act, **the Board substitutes the existing Article 98(i) of the Articles of Association of UPSE**, by the following new Article 98(i) :-

“98. (i) The Board of Directors shall, subject to the prior approval of the Securities and Exchange Board of India, nominate on the Board of Directors not more than 3 (three) persons referred to as Public Representatives who are persons of integrity having necessary professional competence and experience in the areas related to securities market and who are of public eminence in the locality. The persons so nominated **shall continue to hold office till the time new Public Representatives are appointed in their place.**”

It is clarified that the existing two provisos to Article 98(i) will remain as they are and shall appear after the newly added Article 98(i).

[F. NO. SEBI/LE/SE/977/97]

D. R. MEHTA, Chairman